केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों में निम्नलिखित शामिल है:—

1. जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और वायु की गुणवत्ता के सुधार से संबद्ध किसी विषय पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;

2. जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे निष्पादित कराना;

3. राज्य बोर्डों के क्रियाकलापों में समन्वय करना और उनके बीच के विवादों को सुलझाना, राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता देना और उनका मार्गदर्शन करना, जल एवं वायु प्रदूषण को तथा जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से सम्बन्धित अन्वेषण और अनुसंधान क्रियान्वित और प्रायोजित करना;

4. जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के कार्यक्रमों में लगे हुए व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और उसे संगठित करना;

5. जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के बारे में जन-सम्पर्क के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम बनाना;

6. जल एवं वायु प्रदूषण से और उसे प्रभावी निवारण तथा नियंत्रण के लिए प्रकल्पित उपायों से सम्बन्धित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र, संकलित और प्रकाशित करना और मल तथा व्यावसायिक बहिस्राव की अभिक्रिया और व्ययन से सम्बन्धित निर्देशिकाएं, संहिताएं या पथ-प्रदर्शिकाएं तैयार करना और उनसे संबद्ध जानकारी का प्रसार करना;

7. जल एवं वायु प्रदूषण तथा उनके निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित मामलों की सूचना का प्रसार;

8. संबद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से सरिता या कुएं के लिए तथा जल एवं वायु की गुणवत्ता के लिए मानक अधिकथित करना, उसमें उपान्तरण करना या उसे बातिल करना;

9. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

वन संरक्षण अधिनियम के अधीन भूमि का इस्तेमाल

3359. **श्री महेश्वर सिंह:**
श्री शिव चरण सिंह:
श्री संघ प्रिय गौतम:
श्री कैलाश नारायण सारंग:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के बन जाने के बाद भारत सरकार के वन विभाग को राज्य-वार ऐसे कितने मामले प्राप्त हुए है जिनमें भूमि के अन्य उपयोग की अनुमति मांगी है और कितने मामलों में इसकी अनुमति दे दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अधिनियम के बन जाने के बाद विभिन्न राज्यों में विकास-कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**।

(ख) और (ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्तावों की जांच करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से पूरी सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात्, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने के लिए उनकी शीघ्र जांच की जाती है।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 30.11.92 तक प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या और अधिनियम के तहत मंजूर किये गए प्रस्तावों की संख्या

क्र०सं०	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	30.11.92 तक प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	30.11.92 तक मंजूर किये गए प्रस्तावों की सं०
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	170	78
2.	अरूणाचल प्रदेश	73	30
3.	असम	86	56
4.	बिहार	111	40
5.	गोवा	47	11
6.	गुजरात	450	147
7.	हरियाणा	58	33
8.	हिमाचल प्रदेश	222	116
9.	जम्मू व कश्मीर	10	8
10.	कर्नाटक	328	111
11.	केरल	135	79
12.	मध्य प्रदेश	757	285
13.	महाराष्ट्र	696	362
14.	मणिपुर	11	4
15.	मेघालय	25	18
16.	मिजोरम	6	1
17.	नागालैण्ड	2	—
18.	उड़ीसा	164	101
19.	पंजाब	52	21
20.	राजस्थान	150	67
21.	सिक्किम	64	37
22.	तमिलनाडु	203	124
23.	उत्तर प्रदेश	1075	757
24.	त्रिपुरा	59	21
25.	पश्चिमी बंगाल	68	33
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	51	24
27.	दादर व नागर हवेली	9	4
28.	दिल्ली	1	—
29.	दमन व द्वीव	—	—
30.	पांडिचेरी	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	चंडीगढ़	1	—
	कुल	5084	2568

Environment Clearance of Projects from Andhra Pradesh

3360. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the details of the projects from Andhra pradesh which are pending with the Central Government for environmental clearance; and

(b) since when they are pending?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) As on 30th November, 1992 only the following five projects from Andhra Pradesh are awaiting environmental clearance with the date of receipt in the Ministry indicated against each:

Gautam Khani Project, Singareni Collieries Co. Ltd. (SCCL).	February, 1992
Manuguru Opencast IV, SCCL.	August, 1992
Goleti (Longwall) 1&2 Incline Project, SCCL.	October, 1992
Construction of Multi-purpose berth in Outer Harbour of Visakhapatnam Port Trust.	July, 1992